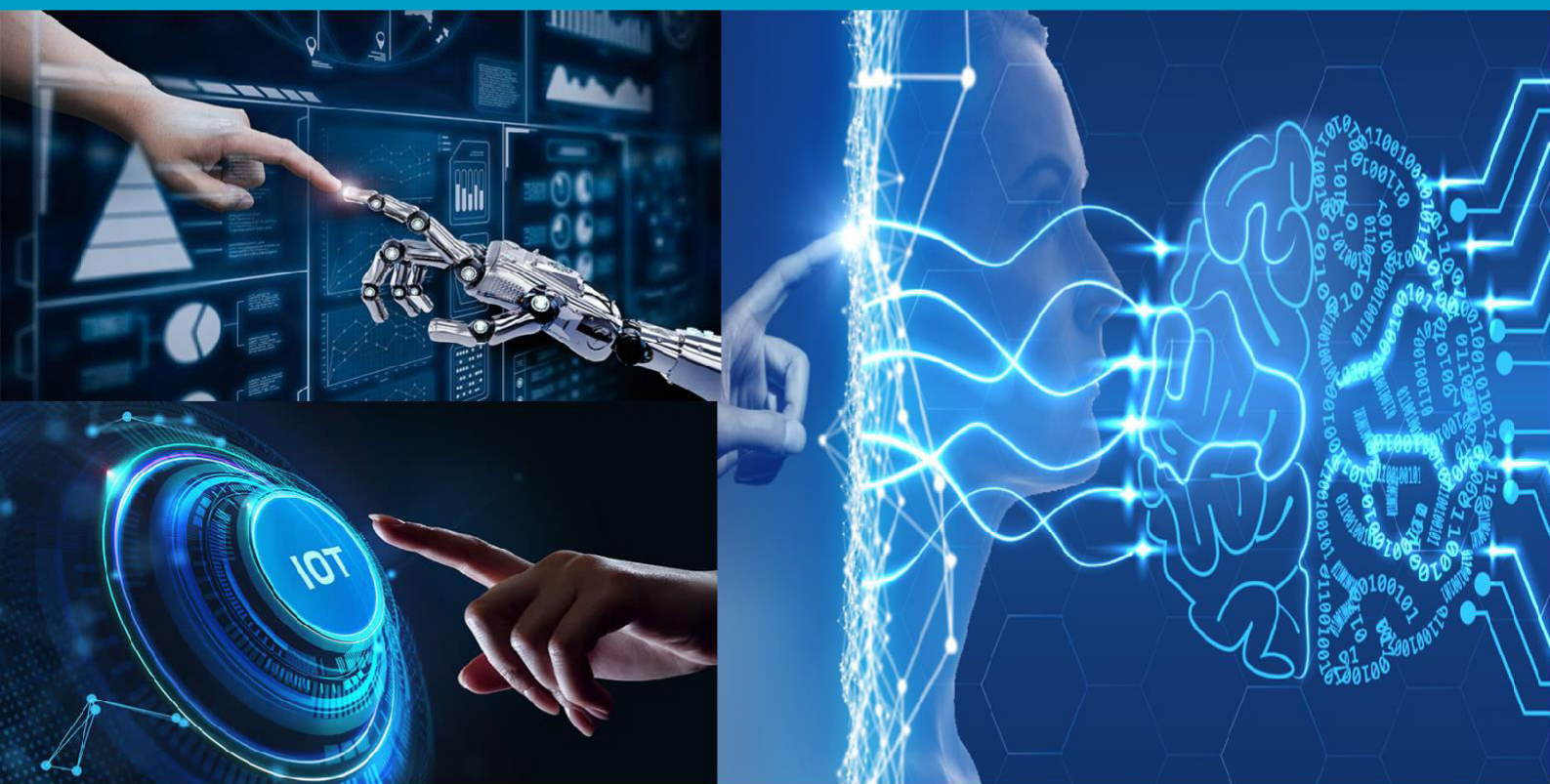




INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Volume 10, Issue 8, August 2023



INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 7.580



+91 99405 72462



+9163819 07438



ijmrsetm@gmail.com



www.ijmrsetm.com

शिक्षा का निजीकरण का विद्यार्थी शिक्षक संबंधो पर प्रभाव

Ravindra Singh Yadav

Ph.D. Scholar, Dept. of Arts and Humanities, Neemrana, Rajasthan, India

सार

पीटर एफ० डेकर के द्वारा सन् 1960 में अपनी पुस्तक 'दॉ ऐज ऑफ डिस्कण्टीन्यूटी' में निजीकरण शब्द के प्रथम बार प्रयोग करने का सन्दर्भ मिलता है। इसके उपरान्त उद्योग व्यापार तथा शिक्षा के क्षेत्रों में इस विचार को व्यावहारिक रूप प्रदान किया जाने लगा। आज शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश अत्यन्त तीव्र गति से बढ़ रहा है तथा इसने एक उद्योग का स्वरूप ले लिया है। निजीकरण से तात्पर्य उन क्रियाओं अथवा उद्यमों, जिन्हें पूर्व में सरकार द्वारा संचालित या प्रबन्धित किया जाता था, को किसी निजी उद्यमी अथवा संस्था को संचालन व प्रबन्धन हेतु हस्तान्तरित करने की प्रक्रिया से है। व्यावहारिक रूप में निजीकरण से तात्पर्य स्वामित्व में एक शिक्षक परिवर्तन अर्थात् सरकारी स्वामित्व के स्थान पर निजी स्वामित्व को स्वीकार करना। निजीकरण सरकारी व्यवस्था में व्याप्त अकर्मण्यता की स्थिति में सुधार लाने की सफलता की परिणति कही जा सकती है।

परिचय

उदारवाद ने ही सत्ता के केन्द्रीकरण का प्रतिनिधित्व करने वाली किसी व्यवस्था का विरोध करने वाली शक्तियों को घनीभूत करके स्वतन्त्रता के विरुद्ध कार्य करने वाली व्यवस्था का खण्डन करने का साहस किया है। सामाजिक क्षेत्र में इसने धर्मनिरपेक्षता को पोषित करने व जाति व्यवस्था का खंडन किया है, आर्थिक क्षेत्र में यह मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है तथा राजनैतिक क्षेत्र में यह संसदीय लोकतन्त्र को पुष्ट करता है। सत्रहवीं तथा अठारहवीं शताब्दी में पहले चर्च तथा फिर राज्य के प्राधिकारवाद के प्रति उदारवादी दृष्टिकोण का उदय हुआ जो उन्नीसवीं एवं बीसवीं शताब्दियों में अन्य क्षेत्रों में फैल गया। शिक्षा का क्षेत्र भी इस परिवर्तन से अछूता नहीं रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में उदारवाद की प्रविष्टि के फलस्वरूप शिक्षा के अर्थ व स्वरूप के साथ-साथ शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रम व विधियों को एक सकारात्मक परिवर्तन के दौर से गुजरना पड़ा है। [1,2]

भारत में निजीकरण की प्रक्रिया सभी क्षेत्रों में प्रवेश कर चुकी है। आज केन्द्र व राज्यों की सरकारों के द्वारा बन्धनकारी नियमों को काफी हद तक निरस्त अथवा शिथिल कर दिया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में यह प्रवृत्ति सभी स्तरों पर अत्यन्त तेजी से विकसित हो रही है। पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तरों पर खुली अनेक निजी शिक्षा संस्थाओं के साथ-साथ अनेक निजी महाविद्यालय व निजी विश्वविद्यालय खोलने के प्रकरण दृष्टान्त बन चुके हैं। सरकार के द्वारा स्ववित्त पोषित मान्यता देने की अवधारणा ने निजीकरण को तेजी से पंख पसारने के अवसर दिये हैं। प्रौद्योगिकी, प्रबन्धन तथा अध्यापक शिक्षा के क्षेत्रों में तो निजी शिक्षा संस्थाओं की बाढ़ सी आ गई है।

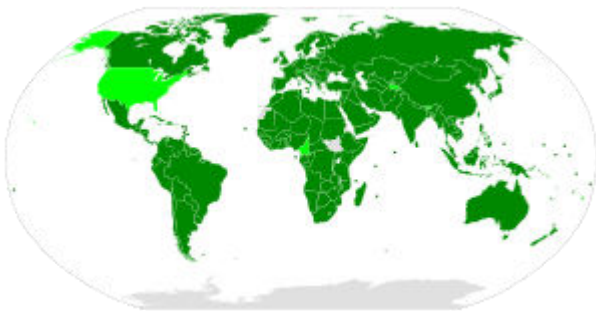
शिक्षा के निजीकरण के लाभ तथा हानि दोनों ही दृष्टिगोचर हो रहे हैं। एक ओर जहाँ कुछ उच्चस्तरीय निजी संस्थाएँ प्रतिस्पर्धा के इस युग में उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की दिशा में सक्रिय हैं वहीं दूसरी ओर अनेक निजी शिक्षा संस्थाएँ अपनी छद्म व स्तरहीन योजनाओं के माध्यम से छात्रों व अभिभावकों का आर्थिक शोषण कर रही हैं।

शिक्षा के अधिकार को कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है, जिसमें आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय समझौता भी शामिल है, जो सभी के लिए मुफ्त, प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को मान्यता देता है, सभी के लिए सुलभ माध्यमिक शिक्षा विकसित करने का दायित्व है। निःशुल्क माध्यमिक शिक्षा की प्रगतिशील शुरूआत के साथ-साथ उच्च शिक्षा तक समान पहुंच विकसित करने का दायित्व, आदर्श रूप से निःशुल्क उच्च शिक्षा की प्रगतिशील शुरूआत के साथ। 2021 में, 171 राज्य अनुबंध के पक्षकार थे।^[1]

2019 में, दुनिया भर में अनुमानित 260 मिलियन बच्चों की स्कूली शिक्षा तक पहुंच नहीं थी, और सामाजिक असमानता एक प्रमुख कारण थी।^[2]

मानवाधिकार मापन पहल^[3] दुनिया भर के देशों के लिए उनकी आय के स्तर के आधार पर शिक्षा के अधिकार को मापती है।^[4]

अंतरराष्ट्रीय कानूनी आधार



विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर कन्वेंशन

राज्यों की पार्टियाँ

वे राज्य जिन्होंने हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन अनुसमर्थन नहीं किया है

जिन राज्यों ने हस्ताक्षर नहीं किये हैं

शिक्षा का अधिकार मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 26 में परिलक्षित होता है, जिसमें कहा गया है:

"हर किसी को शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा मुफ्त होगी, कम से कम प्रारंभिक और मौलिक चरणों में। प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य होगी। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा आम तौर पर उपलब्ध कराई जाएगी और उच्च शिक्षा सभी के लिए समान रूप से सुलभ होगी।" योग्यता। शिक्षा को मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास और मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान को मजबूत करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। यह सभी देशों, नस्लीय या धार्मिक समूहों के बीच समझ, सहिष्णुता और मित्रता को बढ़ावा देगी, और गतिविधियों को आगे बढ़ाएगी। शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र। माता-पिता को यह चुनने का पूर्व अधिकार है कि उनके बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी।"^[5]

शिक्षा के अधिकार को 1960 में शिक्षा में भेदभाव के खिलाफ यूनेस्को कन्वेंशन, 1966 में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध,^{[6][7][8]} 1981 में सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन में फिर से पुष्टि की गई है। महिलाएँ,^[9] बाल अधिकारों पर 1989 कन्वेंशन,^[10] और विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों पर 2006 कन्वेंशन।^[11]

अफ्रीका में, 1981 के मानव और लोगों के अधिकारों पर अफ्रीकी चार्टर^[12] और 1990 के बच्चों के अधिकारों और कल्याण पर अफ्रीकी चार्टर दोनों शिक्षा के अधिकार को मान्यता देते हैं।^[13]

[यूरोप] में, मानवाधिकार पर यूरोपीय कन्वेंशन के 20 मार्च 1952 के पहले प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि शिक्षा के अधिकार को एक मानव अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है और इसे शिक्षा के

अधिकार को स्थापित करने के लिए समझा जाता है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध के अनुसार शिक्षा के अधिकार में सभी के लिए मुफ्त, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, मुफ्त माध्यमिक शिक्षा की प्रगतिशील शुरूआत द्वारा विशेष रूप से सभी के लिए सुलभ माध्यमिक शिक्षा विकसित करने का दायित्व, साथ ही उच्च शिक्षा तक समान पहुंच विकसित करने का दायित्व शामिल है। विशेषकर निःशुल्क उच्च शिक्षा की प्रगतिशील शुरूआत से। शिक्षा के अधिकार में उन व्यक्तियों के लिए बुनियादी शिक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी भी शामिल है जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की है। शिक्षा प्रावधानों तक पहुंच के अलावा, शिक्षा के अधिकार में शैक्षिक प्रणाली के सभी स्तरों पर भेदभाव को खत्म करने, न्यूनतम मानक निर्धारित करने और गुणवत्ता में सुधार करने का दायित्व भी शामिल है। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय स्ट्रासबर्ग में इस मानदंड को उदाहरण के लिए बेल्जियम भाषाई मामले में लागू किया गया है।^[9] यूरोपीय सामाजिक चार्टर का अनुच्छेद 10 व्यावसायिक शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है।^[14]

86वें संशोधन अधिनियम 2002 के तहत भारतीय संविधान के अनुसार, 6-14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है।^[3,5]

यह तर्क दिया गया है कि "अंतर्राष्ट्रीय कानून पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के अधिकार का कोई प्रभावी संरक्षण प्रदान नहीं करता है।"^[15] केवल दो वैश्विक संधियाँ स्पष्ट रूप से प्राथमिक विद्यालय से पहले की शिक्षा का संदर्भ देती हैं। महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन में राज्यों से "प्री-स्कूल में" लड़कियों के लिए समानता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।^[16] और सभी प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों के अधिकारों की सुरक्षा पर कन्वेंशन में, राज्य इस बात पर सहमत हैं कि माता-पिता या बच्चे की "अनियमित स्थिति" के कारण "सार्वजनिक प्री-स्कूल शैक्षणिक संस्थानों" तक पहुंच से इनकार नहीं किया जाएगा। रहने के संबंध में।"^[17] कम स्पष्ट रूप से, आवश्यकता है कि "राज्य पक्ष सभी स्तरों पर एक समावेशी शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करेंगे।"^[18]

2022 में, ह्यूमन राइट्स वॉच ने एक नीति अपनाई जिसमें राज्यों से सभी बच्चों के लिए कम से कम एक वर्ष की निःशुल्क और अनिवार्य, समावेशी, गुणवत्तापूर्ण पूर्व-प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध और सुलभ बनाने का आह्वान किया गया।^[19] ऐसा करते हुए उन्होंने पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के एक वर्ष को शिक्षा के अधिकार के न्यूनतम मूल भाग के रूप में शामिल करने की वकालत की।^[19] उन्होंने सभी राज्यों से योजना में तय किए जाने वाले उचित वर्षों के भीतर, पूर्व-प्राथमिक शिक्षा के आगे के वर्षों के प्रगतिशील कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत कार्य योजना अपनाने का आह्वान किया।^[19]

परिभाषा



मोगादिशु में छात्रा

शिक्षा औपचारिक संस्थागत निर्देशों तक पहुंच है। आम तौर पर, अंतर्राष्ट्रीय उपकरण इस अर्थ में इस शब्द का उपयोग करते हैं और शिक्षा का अधिकार, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार उपकरणों द्वारा संरक्षित है,

मुख्य रूप से एक संकीर्ण अर्थ में शिक्षा को संदर्भित करता है। शिक्षा में भेदभाव के खिलाफ 1960 के यूनेस्को कन्वेंशन के अनुच्छेद 1(2) में शिक्षा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: "शिक्षा के सभी प्रकार और स्तर, (ऐसे सहित) शिक्षा तक पहुंच, शिक्षा के मानक और गुणवत्ता, और वे शर्तें जिनके तहत यह दी जाती है।" [20]



मोगादिशु में एक छात्र अन्य छात्रों को पढ़ा रहा है

व्यापक अर्थ में शिक्षा "उन सभी गतिविधियों का वर्णन कर सकती है जिनके द्वारा एक मानव समूह अपने वंशजों को ज्ञान और कौशल और एक नैतिक संहिता प्रदान करता है जो समूह को जीवित रहने में सक्षम बनाता है"। [20] इस अर्थ में शिक्षा का तात्पर्य दैनिक जीवन के कार्यों को करने के लिए आवश्यक उन कौशलों को अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित करना और विशेष समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक मूल्यों को आगे बढ़ाना है। शिक्षा के व्यापक अर्थ को अंतर्राष्ट्रीय समझ, सहयोग और शांति के लिए शिक्षा और मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता से संबंधित शिक्षा के संबंध में यूनेस्को की 1974 की सिफारिश के अनुच्छेद 1 (ए) में मान्यता दी गई है। [21]

"सामाजिक जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति और सामाजिक समूह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के लाभ के लिए, अपनी संपूर्ण व्यक्तिगत क्षमताओं, दृष्टिकोण, योग्यता और ज्ञान को सचेत रूप से विकसित करना सीखते हैं।" [20]

यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने शिक्षा को एक संकीर्ण अर्थ में "शिक्षण या निर्देश ... विशेष रूप से ज्ञान के प्रसारण और बौद्धिक विकास के लिए" और व्यापक अर्थ में "पूरी प्रक्रिया जिसके द्वारा, किसी भी समाज में, वयस्कों के लिए" के रूप में परिभाषित किया है। उनकी मान्यताओं, संस्कृति और अन्य मूल्यों को युवाओं तक पहुंचाने का प्रयास करें।" [20]

पूर्ति का आकलन

शिक्षा के अधिकार की पूर्ति का आकलन 4ए ढांचे का उपयोग करके किया जा सकता है, जो इस बात पर जोर देता है कि शिक्षा को एक सार्थक अधिकार बनाने के लिए इसे उपलब्ध, सुलभ, स्वीकार्य और अनुकूलनीय होना चाहिए। 4ए फ्रेमवर्क को शिक्षा के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र के पूर्व विशेष प्रतिवेदक, कैटरीना टोमासेवस्की द्वारा विकसित किया गया था, लेकिन जरूरी नहीं कि यह हर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार उपकरण में इस्तेमाल किया जाने वाला मानक हो और इसलिए राष्ट्रीय कानून के तहत शिक्षा के अधिकार के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, इसके लिए यह एक सामान्य मार्गदर्शिका नहीं है। [22]

4ए ढांचे का प्रस्ताव है कि सरकारों को, प्रमुख कर्तव्य-वाहक के रूप में, शिक्षा को उपलब्ध, सुलभ, स्वीकार्य और अनुकूलनीय बनाकर शिक्षा के अधिकार का सम्मान, सुरक्षा और पूरा करना होगा। यह ढांचा शिक्षा प्रक्रिया में अन्य हितधारकों पर भी कर्तव्य डालता है: बच्चा, जो शिक्षा के अधिकार के विशेषाधिकार प्राप्त

विषय के रूप में अनिवार्य शिक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन करने का कर्तव्य है, माता-पिता 'पहले शिक्षक' के रूप में, और पेशेवर शिक्षक, अर्थात् शिक्षक . [22]

4ए को इस प्रकार आगे विस्तृत किया गया है: [23]

- उपलब्धता - सरकारों द्वारा वित्त पोषित, शिक्षा सार्वभौमिक, मुफ्त और अनिवार्य है। छात्रों के लिए पर्याप्त पुस्तकों और सामग्रियों के साथ उचित बुनियादी ढांचा और सुविधाएं होनी चाहिए। इमारतों को सुरक्षा और स्वच्छता दोनों मानकों को पूरा करना चाहिए, जैसे कि स्वच्छ पेयजल होना। सक्रिय भर्ती, उचित प्रशिक्षण और उचित प्रतिधारण विधियों से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि प्रत्येक स्कूल में पर्याप्त योग्य कर्मचारी उपलब्ध हैं। [24]
- पहुंच - लिंग, जाति, धर्म, जातीयता या सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी बच्चों को स्कूल सेवाओं तक समान पहुंच मिलनी चाहिए। शरणार्थियों, बेघरों या विकलांग लोगों के बच्चों सहित हाशिए पर रहने वाले समूहों को शामिल करना सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए; संक्षेप में शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच यानी सभी तक पहुंच होनी चाहिए। जो बच्चे [25] गरीबी में आते हैं उन्हें शिक्षा की पहुंच प्रदान की जानी चाहिए क्योंकि इससे उनकी मानसिक और सामाजिक स्थिति का विकास होता है। [7,8] किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार का अलगाव या प्रवेश से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि किसी भी बाल श्रम या शोषण के खिलाफ उचित कानून मौजूद हैं बच्चों को प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने से रोकना। समुदाय के भीतर के बच्चों के लिए स्कूल उचित दूरी पर होने चाहिए, अन्यथा छात्रों को परिवहन प्रदान किया जाना चाहिए, विशेष रूप से उन्हें जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूल जाने के रास्ते सुरक्षित और सुविधाजनक हों। शिक्षा सभी के लिए सस्ती होनी चाहिए, छात्रों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के पाठ्यपुस्तकें, आपूर्तियाँ और वर्दी प्रदान की जानी चाहिए। [26]
- स्वीकार्यता - प्रदान की गई शिक्षा की गुणवत्ता सभी छात्रों के लिए भेदभाव से मुक्त, प्रासंगिक और सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त होनी चाहिए। छात्रों से किसी विशिष्ट धार्मिक या वैचारिक विचारों के अनुरूप होने की अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। शिक्षण के तरीके वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष होने चाहिए और उपलब्ध सामग्री में विचारों और विश्वासों की एक विस्तृत श्रृंखला प्रतिबिंबित होनी चाहिए। स्कूलों में स्वास्थ्य और सुरक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक सजा को खत्म करना भी शामिल है। कर्मचारियों और शिक्षकों की व्यावसायिकता बनाए रखी जानी चाहिए। [27]
- अनुकूलनशीलता - शैक्षिक कार्यक्रम लचीले होने चाहिए और सामाजिक परिवर्तनों और समुदाय की आवश्यकताओं के अनुसार समायोजित होने में सक्षम होने चाहिए। विकलांग छात्रों को पर्याप्त देखभाल प्रदान करने के साथ-साथ छात्रों को समायोजित करने के लिए स्कूलों द्वारा धार्मिक या सांस्कृतिक छुट्टियों का सम्मान किया जाना चाहिए। [28]

कई अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन और दान विकास के लिए अधिकार-आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके शिक्षा के अधिकार को साकार करने के लिए काम करते हैं। [29]

ऐतिहासिक विकास

यूरोप में, अठारहवीं और उन्नीसवीं सदी के ज्ञानोदय से पहले, शिक्षा माता-पिता और चर्च की जिम्मेदारी थी। फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांति के साथ, शिक्षा को एक सार्वजनिक कार्य के रूप में भी स्थापित किया गया। यह सोचा गया कि राज्य, शिक्षा के क्षेत्र में अधिक सक्रिय भूमिका निभाकर, शिक्षा को सभी के लिए उपलब्ध और सुलभ बनाने में मदद कर सकता है। अब तक शिक्षा मुख्य रूप से उच्च सामाजिक वर्गों के लिए उपलब्ध थी और सार्वजनिक शिक्षा को दोनों क्रांतियों को रेखांकित करने वाले समतावादी आदर्शों को साकार करने के साधन के रूप में माना जाता था। [30]

हालाँकि, न तो अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा (1776) और न ही मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की फ्रांसीसी घोषणा (1789) ने शिक्षा के अधिकार की रक्षा की, क्योंकि उन्नीसवीं शताब्दी में मानवाधिकारों की उदार अवधारणाओं ने परिकल्पना की थी कि माता-पिता प्राथमिक को बरकरार रखेंगे। अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य। यह सुनिश्चित करना राज्य का दायित्व था कि माता-पिता इस कर्तव्य का अनुपालन करें, और कई राज्यों ने स्कूल में उपस्थिति अनिवार्य बनाने के लिए कानून बनाया। इसके अलावा, बच्चों को स्कूल जाने के लिए सुनिश्चित करने के लिए, बच्चों को प्रतिदिन नियोजित किए जाने वाले घंटों की संख्या को सीमित करने के लिए बाल श्रम कानून बनाए गए थे। राज्य भी पाठ्यक्रम के कानूनी विनियमन में शामिल हो गए और न्यूनतम शैक्षिक मानक स्थापित किये।^[31]

ऑन लिबर्टी में जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा है कि "राज्य द्वारा स्थापित और नियंत्रित शिक्षा केवल अस्तित्व में होनी चाहिए, यदि वह अस्तित्व में है, तो कई प्रतिस्पर्धी प्रयोगों में से एक के रूप में, दूसरों को ऊपर रखने के लिए उदाहरण और प्रोत्साहन के उद्देश्य से किया जाता है। उत्कृष्टता के निश्चित मानक।" उन्नीसवीं सदी के उदारवादी विचारकों ने शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की बहुत अधिक भागीदारी के खतरों की ओर इशारा किया, लेकिन चर्च के प्रभुत्व को कम करने और अपने माता-पिता के खिलाफ बच्चों के शिक्षा के अधिकार की रक्षा के लिए राज्य के हस्तक्षेप पर भरोसा किया। उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्ध में, शैक्षिक अधिकारों को घरेलू अधिकारों के बिल में शामिल किया गया।^[31] 1849 पॉल्सकिर्चनवरफ्रासुंग, जर्मन साम्राज्य का संविधान, बाद के यूरोपीय संविधानों को दृढ़ता से प्रभावित किया और शिक्षा के अधिकार के अपने बिल के अनुच्छेद 152 से 158 तक समर्पित किया। संविधान ने शिक्षा को चर्च से स्वतंत्र राज्य के कार्य के रूप में मान्यता दी। उस समय उल्लेखनीय बात यह थी कि संविधान ने गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा के अधिकार की घोषणा की, लेकिन संविधान में स्पष्ट रूप से राज्य को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय संविधान ने नागरिकों के स्कूल खोलने और संचालित करने और घर पर शिक्षा प्रदान करने के अधिकारों की रक्षा की। संविधान ने विज्ञान और शिक्षण की स्वतंत्रता भी प्रदान की, और इसने हर किसी को अपना व्यवसाय चुनने और उसके लिए प्रशिक्षण लेने के अधिकार की गारंटी दी।^[32]

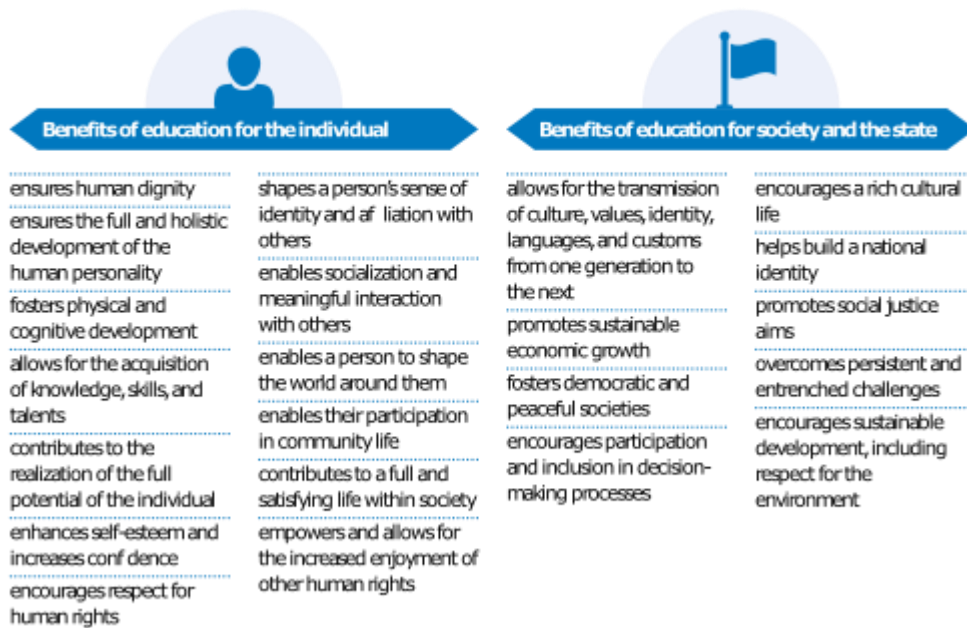
उन्नीसवीं सदी में समाजवादी सिद्धांत का विकास भी हुआ, जिसमें माना गया कि राज्य का प्राथमिक कार्य सरकारी हस्तक्षेप और विनियमन के माध्यम से समुदाय की आर्थिक और सामाजिक भलाई सुनिश्चित करना था। समाजवादी सिद्धांत ने माना कि व्यक्तियों के पास राज्य के विरुद्ध बुनियादी कल्याण सेवाओं के दावे थे और शिक्षा को इन कल्याणकारी अधिकारों में से एक के रूप में देखा गया था। यह उस समय के उदारवादी सिद्धांत के विपरीत था, जो गैर-राज्य अभिनेताओं को शिक्षा का प्रमुख प्रदाता मानता था। 1917 में मैक्सिकन संविधान मुफ्त और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा की गारंटी देने वाला पहला संविधान था।^[9,10]^[33] बाद में, समाजवादी आदर्शों को 1936 के सोवियत संविधान में प्रतिष्ठापित किया गया, जो ऐसी शिक्षा प्रदान करने के लिए राज्य के संबंधित दायित्व के साथ शिक्षा के अधिकार को मान्यता देता है। संविधान ने सभी स्तरों पर मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, राज्य छात्रवृत्ति की एक प्रणाली और राज्य उद्यमों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की गारंटी दी। इसके बाद, शिक्षा का अधिकार समाजवादी राज्यों के संविधानों में दृढ़ता से प्रदर्शित हुआ।^[32] एक राजनीतिक लक्ष्य के रूप में, शिक्षा के अधिकार को एफडी रूजवेल्ट के 1944 के दूसरे अधिकार विधेयक पर भाषण में घोषित किया गया था।

व्यक्तियों, समाज और राज्य के लिए शिक्षा की भूमिका

शिक्षा अपने सभी रूपों (अनौपचारिक, गैर- औपचारिक और औपचारिक) में सभी व्यक्तियों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। शिक्षा के उद्देश्य, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून (आईएचआरएल) में निर्धारित किया गया है, सभी व्यक्ति के अधिकारों और गरिमा की प्राप्ति के लिए निर्देशित हैं।^[34] इनमें अन्य बातों के अलावा, मानवीय गरिमा और मानव व्यक्तित्व का पूर्ण और समग्र विकास सुनिश्चित करना शामिल है; शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास को बढ़ावा देना; ज्ञान, कौशल और प्रतिभा के

अधिग्रहण की अनुमति देना; व्यक्ति की पूर्ण क्षमता की प्राप्ति में योगदान; आत्म-सम्मान बढ़ाना और आत्मविश्वास बढ़ाना; मानवाधिकारों के प्रति सम्मान को प्रोत्साहित करना; किसी व्यक्ति की पहचान और दूसरों के साथ जुड़ाव की भावना को आकार देना; दूसरों के साथ समाजीकरण और सार्थक बातचीत को सक्षम बनाना; किसी व्यक्ति को अपने आसपास की दुनिया को आकार देने में सक्षम बनाना सामुदायिक जीवन में उनकी भागीदारी को सक्षम बनाता है; समाज के भीतर पूर्ण और संतुष्ट जीवन में योगदान देना; और अन्य मानवाधिकारों के आनंद को बढ़ाने के लिए सशक्त बनाना और अनुमति देना।^[35]

The multiple benefits of education



शिक्षा के अनेक लाभ

शिक्षा राज्य और समाज के लिए भी परिवर्तनकारी है। सबसे महत्वपूर्ण तंत्रों में से एक के रूप में जिसके द्वारा सामाजिक समूहों, विशेष रूप से स्वदेशी लोगों और अल्पसंख्यकों को पीढ़ी-दर-पीढ़ी बनाए रखा जाता है, भाषा, संस्कृति, पहचान, मूल्यों और रीति-रिवाजों को आगे बढ़ाया जाता है, शिक्षा भी उन प्रमुख तरीकों में से एक है जिससे राज्य सुनिश्चित कर सकते हैं। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक हित।^[35]

एक समाज और राज्य के भीतर शिक्षा की मुख्य भूमिका है: ^[35]

- संस्कृति, मूल्यों, पहचान, भाषाओं और रीति-रिवाजों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करने की अनुमति दें;
- सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना;
- लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण समाजों को बढ़ावा देना;
- निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भागीदारी और समावेशन को प्रोत्साहित करना;
- समृद्ध सांस्कृतिक जीवन को प्रोत्साहित करें;
- राष्ट्रीय पहचान बनाने में मदद करें;
- सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना ;
- निरंतर और उलझी हुई चुनौतियों पर काबू पाएं;[11,12]
- पर्यावरण के प्रति सम्मान सहित सतत विकास को प्रोत्साहित करें।^[35]

कार्यान्वयन



मनीला साइंस हाई स्कूल, मनीला, फिलीपींस

अंतर्राष्ट्रीय कानून पूर्व- प्राथमिक शिक्षा के अधिकार की रक्षा नहीं करता है और अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेज़ आम तौर पर इस स्तर पर शिक्षा के संदर्भ को छोड़ देते हैं।^[36] मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कहा गया है कि हर किसी को शिक्षा का अधिकार है, इसलिए यह अधिकार सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, हालांकि बच्चों को मुख्य लाभार्थी माना जाता है।^[37]

शिक्षा के अधिकारों को तीन स्तरों में विभाजित किया गया है:

- प्राथमिक (मौलिक या मौलिक) शिक्षा। यह किसी भी बच्चे के लिए उनकी राष्ट्रीयता, लिंग, जन्म स्थान या किसी अन्य भेदभाव की परवाह किए बिना अनिवार्य और निःशुल्क होगा। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध की पुष्टि करने पर राज्यों को दो साल के भीतर मुफ्त प्राथमिक शिक्षा प्रदान करनी होगी।
- माध्यमिक (या यूडीएचआर में प्राथमिक, तकनीकी और व्यावसायिक) शिक्षा आम तौर पर उपलब्ध और सुलभ होनी चाहिए।
- विश्वविद्यालय स्तर पर क्षमता के अनुरूप शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अर्थात्, जो कोई भी आवश्यक शिक्षा मानकों को पूरा करता है, उसे विश्वविद्यालय जाने में सक्षम होना चाहिए।

माध्यमिक और उच्च शिक्षा दोनों को "हर उचित माध्यम से, और विशेष रूप से मुफ्त शिक्षा की प्रगतिशील शुरुआत द्वारा" सुलभ बनाया जाएगा।^[38]

अनिवार्य शिक्षा

राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के अधिकार की प्राप्ति अनिवार्य शिक्षा , या अधिक विशेष रूप से मुफ्त अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, जैसा कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध दोनों में कहा गया है।^{[6] [39]}

बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार



क्यूएआईएस में मोटेसरी अर्ली चाइल्डहुड में



भूगोल
सैनिक और स्कूली बच्चे

बहरीन में क्षेत्रीय सक्रिय शिक्षण संस्थान में अमेरिकी

बचपन से ही सभी बच्चों के अधिकार 1948 के मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा से उत्पन्न होते हैं। अनुच्छेद 1 में घोषित घोषणा: 'सभी मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुए हैं और गरिमा और अधिकारों में समान हैं।' घोषणा में कहा गया है कि मानवाधिकार जन्म से शुरू होते हैं और बचपन विशेष देखभाल और सहायता की मांग करने वाला काल है [कला। 25 (2)]। 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा में इस बात की पुष्टि की गई कि: 'मानव जाति को बच्चे को जो कुछ भी देना है वह उसका ऋणी है', जिसमें शिक्षा भी शामिल है। इसे 1966 के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध द्वारा बढ़ाया गया था जिसमें कहा गया है कि: 'शिक्षा को मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास और उसकी गरिमा की भावना के लिए निर्देशित किया जाएगा, और सम्मान को मजबूत किया जाएगा। मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता. [कला। 13 (1)]^[40]

1990 में थाईलैंड के जोमटियन में अपनाई गई सभी के लिए शिक्षा पर विश्व घोषणा (ईएफए) के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि: 'सीखना जन्म से शुरू होता है [...] इसके लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा की आवश्यकता होती है।' एक दशक बाद, ईएफए पर कार्रवाई के लिए डकार फ्रेमवर्क ने छह लक्ष्य स्थापित किए, जिनमें से पहला था: 'विशेष रूप से सबसे कमजोर और वंचित बच्चों के लिए प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा का विस्तार और सुधार करना।' अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सभी उम्र के बच्चों को शोषण और उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण को खतरे में डालने वाले कार्यों से सुरक्षा पर भी जोर दिया गया है। रोजगार की न्यूनतम आयु (1973) पर कन्वेंशन संख्या 138 और बाल श्रम के सबसे खराब रूपों के उन्मूलन के लिए निषेध और तत्काल कार्रवाई पर संख्या 182 (1999) में। संयुक्त राष्ट्र ने 1959 में महासभा द्वारा सर्वसम्मति से अपनाई गई बाल अधिकारों की घोषणा द्वारा ऐसे प्रयासों में योगदान दिया।^[40]

शिक्षा के अधिकार की दिशा में कई गैर सरकारी संगठन काम कर रहे हैं। द्वारा शुरू किए गए ऐसे प्लेटफार्मों में से एक है जो बताता है कि शिक्षा बुनियादी अधिकार है और EClickKart इस दिशा में काम कर रहा है।^[42]

शिक्षा के अधिकार पर निजीकरण का प्रभाव

शिक्षा के निजीकरण का कुछ सामाजिक समूहों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, सीखने के अवसरों की उपलब्धता में वृद्धि, माता-पिता की अधिक पसंद और पाठ्यक्रम की विस्तृत श्रृंखला के रूप में। हालाँकि, सार्वजनिक अधिकारियों (बिना लाइसेंस वाले स्कूल, अप्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति और गुणवत्ता आश्वासन^[13,15] की अनुपस्थिति) द्वारा अपर्याप्त या अपर्याप्त निगरानी और विनियमन के परिणामस्वरूप इसके नकारात्मक प्रभाव भी हो सकते हैं, जिससे सामाजिक एकजुटता और एकजुटता के लिए संभावित जोखिम हो सकते हैं। विशेष चिंता का विषय: "हाशिए पर रहने वाले समूह अधिकांश सकारात्मक प्रभावों का आनंद लेने में विफल रहते हैं और निजीकरण के नकारात्मक प्रभावों का अनुपातहीन बोझ भी सहन करते हैं।"^[43] इसके अलावा, निजी प्रदाताओं द्वारा मांगी जाने वाली अनियंत्रित फीस शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच को कमजोर कर सकती है। आम तौर पर, इसका अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा के अधिकार के आनंद और समान शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।^[44]

पूरक निजी शिक्षण, या 'छाया शिक्षा', जो शिक्षा के निजीकरण के एक विशिष्ट आयाम का प्रतिनिधित्व करती है, दुनिया भर में भी बढ़ रही है।^[45] अक्सर खराब कामकाजी स्कूल प्रणालियों का एक लक्षण,^[46] निजी शिक्षण, निजी शिक्षा की अन्य अभिव्यक्तियों की तरह, शिक्षार्थियों और उनके शिक्षकों के लिए सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव डाल सकता है। एक ओर, शिक्षण को धीमी गति से सीखने वालों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जा सकता है और शिक्षक अपने स्कूल के वेतन को पूरा कर सकते हैं। दूसरी ओर, निजी ट्यूशन की फीस घरेलू आय के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व कर सकती है, विशेष रूप से गरीबों के बीच, और इसलिए सीखने के अवसरों में असमानताएं पैदा हो सकती हैं। और यह तथ्य कि कुछ शिक्षक निजी ट्यूशन में अधिक प्रयास कर सकते हैं और अपने नियमित कर्तव्यों की उपेक्षा कर सकते हैं, स्कूल में शिक्षण और सीखने की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं।^[47] छाया शिक्षा की वृद्धि, व्यक्तियों और परिवारों द्वारा जुटाए गए वित्तीय संसाधन, और संभावित शिक्षक कदाचार और भ्रष्टाचार के बारे में चिंताएं शिक्षा के कुछ मंत्रालयों को इस घटना को विनियमित करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित कर रही हैं।^{[44][47]}

सामाजिक असमानता



लड़कियों का स्कूल, 2015।

खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान में

वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर अनुमानित 260 मिलियन बच्चों की स्कूली शिक्षा तक पहुंच नहीं थी।^[48]

महिला शिक्षा

21वीं सदी में, लैंगिक असमानता अभी भी शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच में बाधा है।^[49]^[50] महिला लिंग भूमिका के प्रति रूढ़िवादी दृष्टिकोण महिलाओं और लड़कियों द्वारा शिक्षा के अधिकार के पूर्ण उपयोग को चुनौती देता है।^[51]



मलाला यूसुफजई, महिला शिक्षा के लिए कार्यकर्ता

विश्व में 750 मिलियन निरक्षर वयस्कों में से दो-तिहाई महिलाएँ होने का अनुमान है। यह लैंगिक असमानता, स्त्रीद्वेषी हिंसा के साथ-साथ विवाह और गर्भावस्था के कारण है, जो अक्सर गरीबी और भौगोलिक अलगाव से जुड़ा होता है।^[51] 21वीं सदी के दूसरे दशक में, महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच के अधिकार की वकालत पाकिस्तानी नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई की सक्रियता के माध्यम से एक वैश्विक आंदोलन बन गई।^[52]^[53]

कोविड-19

COVID-19 महामारी ने दुनिया के 90% से अधिक छात्रों को प्रभावित किया और शिक्षा तक पहुंच में सामाजिक असमानता में वृद्धि के लिए जिम्मेदार था। महामारी के तत्काल बाद आई वैश्विक मंदी ने शिक्षा वित्त पोषण पर गंभीर परिणाम उत्पन्न किए, जिससे शिक्षा के समान अधिकार पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा।^[54]^[55]^[56] विश्व स्तर पर, महामारी के दौरान, लिंग, वर्ग और जातीयता के मार्करों ने खुद को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बुनियादी अधिकारों तक पहुंच में भेद्यता के कारक के रूप में प्रस्तुत किया।^[57]^[58]



असम के एक स्कूल में बच्चों को

निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का वितरण

ई-लर्निंग का ऐतिहासिक उद्देश्य शिक्षा पहुंच के लोकतंत्रीकरण की ओर चलने के बावजूद, इसकी गुणवत्ता के आधार पर, इस अधिकार की प्राप्ति में कठिनाई हो सकती है। छात्रों के पास सांस्कृतिक पूंजी, पारिवारिक समर्थन और भौतिक स्थितियों (गुणवत्तापूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इंटरनेट तक पहुंच सहित) की कमी है, शिक्षा की इस पद्धति के कारण उनकी शिक्षा तक पहुंच बाधित हुई है। कोविड-19 महामारी के दौरान कक्षा शिक्षण की वापसी ने स्वास्थ्य के अधिकार और शिक्षा के अधिकार के बीच संघर्ष उत्पन्न कर दिया

। महामारी के पूरी तरह नियंत्रण में आने से पहले स्कूल लौटने से, छात्र SARS-CoV-2 के संपर्क में आ गए। महामारी से जुड़ा एक और पहलू, जो स्वास्थ्य के अधिकार से भी संबंधित है, वह है छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान।

विचार-विमर्श

निजीकरण व्यवसाय, उद्यम, एजेंसी या सार्वजनिक सेवा के स्वामित्व के सार्वजनिक क्षेत्र (राज्य या सरकार) से निजी क्षेत्र (निजी लाभ के लिए संचालित व्यवसाय) या निजी गैर-लाभ संगठनों के पास स्थानांतरित होने की घटना या प्रक्रिया है। एक व्यापक अर्थ में, निजीकरण राजस्व संग्रहण तथा कानून प्रवर्तन जैसे सरकारी प्र कार्यों सहित, सरकारी प्र कार्यों के निजी क्षेत्र में स्थानांतरण को संदर्भित करता है।^[1]

शब्द "निजीकरण" का दो असंबंधित लेनदेनों के वर्णन के लिए भी उपयोग किया गया है। पहला खरीद है, जैसे किसी सार्वजनिक निगम या स्वामित्व वाली कंपनी के स्टॉक के सभी शेयर बहुमत वाली कंपनी द्वारा खरीदा जाना, सार्वजनिक रूप से कारोबार वाले स्टॉक का निजीकरण है, जिसे प्रायः निजी इक्विटी भी कहते हैं। दूसरा है एक पारस्परिक संगठन या सहकारी संघ का पारस्परिक समझौता रद्द कर के एक संयुक्त स्टॉक कंपनी बनाना।^[2]

प्राचीन ग्रीस से निजीकरण का एक लंबा इतिहास मिलता है जब सरकारों ने लगभग सब कुछ निजी क्षेत्र को अनुबंधित कर दिया था।^[5] रोमन गणराज्य में कर संग्रह (कर-पालन), सैन्य आपूर्ति (सैन्य ठेकेदार), धार्मिक बलिदान और निर्माण सहित अधिकतर सेवाएं निजी व्यक्तियों और कंपनियों द्वारा दी जाती थीं। हालांकि, रोमन साम्राज्य ने राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम भी बनाए थे- उदाहरण के लिए, अधिकांश अनाज का उत्पादन अंततः सम्राट के स्वामित्व वाली भूसंपत्ति पर होता था। कुछ विद्वानों का मत है कि नौकरशाही की लागत रोमन साम्राज्य के पतन के कारणों में से एक था।^[5]

ब्रिटेन में आम भूमि के निजीकरण को बाड़े के रूप में संदर्भित किया जाता है (स्कॉटलैंड में तराई स्वीकृतियों और पर्वतीय-भूमि स्वीकृतियों के रूप में)। इस प्रकार का महत्वपूर्ण निजीकरण उस देश में औद्योगिक क्रांति के समकालीन 1760 से 1820 में हुआ था।

अभी हाल के समय में, विंस्टन चर्चिल की सरकार ने 1950 में ब्रिटिश इस्पात उद्योग का निजीकरण किया था और पश्चिम जर्मनी की सरकार ने 1961 में वोक्सवैगन में अपनी बहुमत हिस्सेदारी के सार्वजनिक शेयरों को छोटे निवेशकों को बेचने सहित, बड़े पैमाने पर निजीकरण प्रारंभ किया था।^[6] 1970 के दशक में जनरल पिनोशे ने चिली में महत्वपूर्ण निजीकरण कार्यक्रम लागू किया था। हालांकि, 1980 के दशक में ब्रिटेन में मार्गरेट थैचर और संयुक्त राज्य अमेरिका में रонаल्ड रीगन के नेतृत्व में निजीकरण ने वैश्विक गति हासिल की। ब्रिटेन में इस की पराकाष्ठा 1993 में थैचर के उत्तराधिकारी जॉन मेजर द्वारा ब्रिटिश रेल के निजीकरण के रूप में हुई, ब्रिटिश रेल को पूर्व में निजी कंपनियों का राष्ट्रीयकरण करके गठित किया गया था।^[1,17]

विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए अमेरिकन एजेंसी, जर्मन टूहेंड तथा अन्य सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से, 1990 के दशक में पूर्वी और मध्य यूरोप में तथा पूर्व सोवियत यूनियन में सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों का निजीकरण किया गया।

एक प्रमुख रूप से चल रहे निजीकरण में, जो कि जापान डाक सेवा से संबंधित है, में जापानी डाक सेवा तथा दुनिया का सबसे बड़ा बैंक शामिल हैं। कई पीढ़ियों की बहस के बाद, जूनीचिरो कोइजुमी के नेतृत्व में यह निजीकरण 2007 में शुरू हुआ था। निजीकरण की इस प्रक्रिया के 2017 तक खत्म होने की आशा है।¹

विधियां

निजीकरण की मुख्य रूप से चार विधियां हैं:

1. शेयर इश्यू प्राइवेटाइजेशन (एसआईपी (SIP)) - स्टॉक बाजार में शेयर बेच कर
2. संपत्ति बिक्री निजीकरण - आम तौर से नीलामी द्वारा या टूहेंड मॉडल के प्रयोग द्वारा एक सामरिक निवेशक को संपूर्ण संगठन (या इसका भाग) बेच कर.
3. निजीकरण वाउचर - प्रायः स्वामित्व के शेयर सभी नागरिकों को मुफ्त या बहुत कम कीमत पर वितरित कर के.
4. नीचे से निजीकरण - पूर्व समाजवादी देशों में नए निजी कारोबारों की शुरुआत द्वारा.

बिक्री विधि का चयन पूंजी बाजार, राजनीतिक एवं कंपनी-विशेष के कारकों पर निर्भर करता है। जब पूंजी बाजार कम विकसित होते हैं तथा आय असमानता कम होती है, तब एसआईपी (SIP) की संभावना अधिक होती है। शेयर निर्गम, तरलता बढ़ा कर तथा (संभावित) आर्थिक विकास द्वारा घरेलू पूंजी बाजार को विस्तृत और सघन कर सकते हैं, किंतु यदि अपर्याप्त रूप से विकसित हैं, तो अधिक खरीददार मिलने कठिन होंगे तथा लेनदेन लागत (जैसे अवमूल्यन की आवश्यकता) अधिक हो सकती है। इस कारण से, कई सरकारें अधिक विकसित और तरलता युक्त बाजारों में सूचीबद्ध होने का विकल्प चुनती हैं, उदाहरण के लिए यूरोनेक्स्ट, तथा लंदन, न्यूयॉर्क और हांगकांग के शेयर बाजार.

अत्यधिक राजनीतिक और मुद्रा जोखिम से विदेशी निवेशकों के भयभीत होने के परिणामस्वरूप विकासशील देशों में संपदा बिक्री होना अधिक आम है।

वाउचर निजीकरण मुख्य रूप से केंद्रीय और पूर्वी यूरोप की संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं जैसे रूस, पोलैंड, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया में हुआ है। इसके अतिरिक्त, नीचे से निजीकरण संक्रमण अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास की एक महत्वपूर्ण विधि है/रही है।

शेयर या संपत्ति-बिक्री निजीकरण का एक बड़ा लाभ यह है कि बोलीदाताओं के द्वारा सबसे अधिक मूल्य की पेशकश कर प्रतिस्पर्धा करने से कर राजस्व के अलावा राज्य के लिए आय का निर्माण होता है। दूसरी तरफ, वाउचर निजीकरण में, भागीदारी और शामिल किए जाने की एक वास्तविक भावना पैदा करते हुए आम जनता को संपत्ति का वास्तविक हस्तांतरण हो सकता है। अगर वाउचर के हस्तांतरण की अनुमति दी जाती है, तो कंपनियों द्वारा इनके भुगतान करने की पेशकश के साथ एक वाउचर बाजार का सृजन हो सकता है।

भिन्न दृष्टिकोण

समर्थक

निजीकरण के समर्थकों का मानना है कि निजी बाजार कारक मुक्त बाजार प्रतियोगिता के कारण सरकारों की तुलना में अधिक कुशलता से माल अथवा सेवा प्रदान कर सकते हैं। सामान्यतः यह तर्क दिया जाता है कि समय के साथ इससे कीमतें कम होंगी, गुणवत्ता में सुधार होगा, अधिक विकल्प मिलेंगे, भ्रष्टाचार कम होगा, लाल फीता शाही नहीं होगी और त्वरित वितरण होगा। कई समर्थक यह तर्क नहीं देते हैं कि हर चीज का निजीकरण किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक, बाजार की विफलता और प्राकृतिक एकाधिकार समस्याजनक हो सकते हैं। हालांकि, कुछ ऑस्ट्रियाई विचारधारा के अर्थशास्त्री और अराजक-पूंजीपति चाहते हैं कि रक्षा और विवाद समाधान सहित राज्य के हर कार्य का निजीकरण होना चाहिए।

निजीकरण के लिए बुनियादी आर्थिक तर्क यह दिया जाता है कि अपने उद्यमों को सुनिश्चित रूप से अच्छी तरह चलाने के लिए सरकारों के पास बहुत ही कम प्रोत्साहन होते हैं। राज्य के एकाधिकार में, तुलना की कमी एक समस्या है। तुलना करने के लिए प्रतियोगी के उपस्थित न होने से, यह कहना बहुत कठिन होता है

कि उद्यम कुशल है या नहीं। दूसरे यह कि केंद्र सरकार प्रशासन और मतदाता जिन्होंने उन्हें चुना है, को इतने सारे और अलग-अलग उद्यमों की क्षमता का मूल्यांकन करने में कठिनाई होती है। एक निजी मालिक, अक्सर जिसे विशेषज्ञता और एक निश्चित औद्योगिक क्षेत्र के बारे में अधिक ज्ञान होता है, मूल्यांकन कर सकता है और कम संख्या के उद्यमों में अधिक कुशलता से प्रबंधन को दंडित या पुरस्कृत कर सकता है। इसके अतिरिक्त, एक निजी मालिक के विपरीत, सरकारें राजस्व अपर्याप्त होने पर, कराधान से या केवल मुद्रा का मुद्रण करके धन जुटा सकती हैं।

यदि निजी और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम एक दूसरे के विरुद्ध प्रतियोगिता करते हैं तो, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को निजी उद्यमों की तुलना में सस्ती दर पर ऋण बाजार से ऋण मिल जाता है, क्योंकि राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों के पीछे अंततः राज्य के कराधान और छापेखाने की ताकत होती है, जिससे उन्हें अनुचित लाभ मिलता है।

राज्य के स्वामित्व वाली एक अलाभदायक कंपनी का निजीकरण करने से, वह कंपनी लाभोत्पादक बनने के लिए कीमतें बढ़ा सकती है। हालांकि, इस से घाटे की पूर्ति के लिए सरकार को करों से प्राप्त धन को इसमें लगाने की जरूरत नहीं रहेगी।

निजीकरण के समर्थक निम्नलिखित तर्क देते हैं:

- कार्यप्रदर्शन (परफॉर्मेंस). राज्य-संचालित उद्योगों का रुख नौकरशाही की ओर होता है। जब एक राजनैतिक सरकार का कमजोर कार्य प्रदर्शन राजनैतिक रूप से संवेदनशील हो जाता है, तब ही वह एक कार्य में सुधार करने के लिए प्रेरित होती है और ऐसा कोई सुधार अगले शासन द्वारा आसानी से उलटा जा सकता है।¹
- दक्षता में वृद्धि. निजी कंपनियों और फर्मों के पास एक ग्राहक आधार तक पहुंचने और मुनाफा बढ़ाने हेतु अधिक माल और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए अधिक प्रोत्साहन होते हैं। सरकार के पूर्ण बजट में अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों का ध्यान रखा जाता है, अतः पर्याप्त वित्त पोषण के अभाव में इसके सार्वजनिक उद्यम अधिक उत्पादक नहीं हो सकते. (ध्यान दें: हालांकि सैमुएलसन शर्त के अनुसार, सार्वजनिक संगठनों की प्रवृत्ति अधिक सार्वजनिक माल और सेवा के उत्पादन की होती है। इसके अतिरिक्त, क्योंकि निजी कंपनियां सीमांत निजी लाभ वक्र के अनुसार माल और सेवाओं का उत्पादन करती हैं, इसलिए निजी कंपनियों के पास कम उत्पादन करने का एक प्रोत्साहन होता है।)
- विशेषज्ञता. एक निजी व्यापार सभी संबंधित मानवीय और वित्तीय संसाधनों को विशिष्ट कार्यों की ओर केंद्रित करने की क्षमता रखता है। एक राज्य के स्वामित्व वाली फर्म को अपने सामान्य उत्पादों को जनसंख्या में लोगों की बहुत बड़ी संख्या को उपलब्ध कराना होता है, इसलिए उसके पास अपने उत्पादों और सेवाओं का विशिष्टीकरण करने के लिए आवश्यक संसाधन नहीं होते हैं।
- सुधार इसके विपरीत, सरकार उन कंपनियों के मामले में भी राजनीतिक संवेदनशीलता और विशेष हितों की वजह से सुधारों को टाल सकती है - जो अच्छी तरह से चल रही हैं और अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की बेहतर सेवा कर रही हैं।
- भ्रष्टाचार. एक राज्य के एकाधिकार वाले प्रकार्य भ्रष्टाचार प्रवृत्त होते हैं, निर्णय आर्थिक कारणों की बजाय मुख्य रूप से राजनीतिक कारणों से निर्णय-कर्ता के व्यक्तिगत लाभ (यानी "रिश्वत") के लिए, किए जाते हैं। एक सरकारी निगम में भ्रष्टाचार (या प्रधान-एजेंट मुद्दे) चालू परिसंपत्ति के प्रवाह और कंपनी के कार्यप्रदर्शन को प्रभावित करता है, जबकि निजीकरण की प्रक्रिया के दौरान होने वाला भ्रष्टाचार एक बार होने वाली घटना है और चालू नकद प्रवाह या कंपनी के कार्य प्रदर्शन को प्रभावित नहीं करता।
- उत्तरदायित्व. निजी स्वामित्व वाली कंपनियों के प्रबंधक अपने मालिकों/शेयरधारकों और उपभोक्ता के प्रति जवाबदेह होते हैं और केवल वहीं टिक और पनप सकते हैं जहां जरूरतें पूरी हो रही हों। सार्वजनिक स्वामित्व वाली कंपनियों के प्रबंधकों को और अधिक व्यापक समुदाय के लिए तथा

राजनीतिक "हितधारकों" के प्रति जवाबदेह होना आवश्यक हैं। यह उनकी सीधे और विशेष रूप से अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की सेवा करने की क्षमता को कम कर सकता है और पूर्वाग्रह के कारण निवेश के निर्णय दूसरे लाभदायक क्षेत्रों से अलग हो सकते हैं।

- नागरिक स्वतंत्रता की समस्या. एक राज्य द्वारा नियंत्रित कंपनी की पहुंच उस जानकारी या संपत्ति तक हो सकती है, जिसे असंतुष्टों या कोई भी व्यक्ति जो उनकी नीतियों से असहमत है, के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है।
- लक्ष्य. एक राजनैतिक सरकार की प्रवृत्ति आर्थिक के बजाय राजनीतिक लक्ष्यों के लिए उद्योग या कंपनी को चलाने की होती है।
- पूंजी निजी स्वामित्व वाली कंपनियां कभी कभी अधिक आसानी से वित्तीय बाजारों में पूंजी निवेश बढ़ा सकती हैं जब इस तरह के स्थानीय बाजार मौजूद होते हैं और उपयुक्त रूप से तरल होते हैं। जबकि निजी कंपनियों के लिए ब्याज दरें अक्सर सरकारी ऋण की तुलना में अधिक होती हैं, यह निजी कंपनियों द्वारा देश के समग्र ऋण जोखिम के साथ उन्हें सब्सिडी देने की बजाय, कुशल निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक उपयोगी व्यवरोध के रूप में कार्य कर सकता है। तब निवेश के फैसले बाजार की ब्याज दरों द्वारा शासित होते हैं। राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों को अन्य सरकारी विभागों और विशेष हितों की मांग के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होती है। दोनों में से किसी भी स्थिति में, छोटे बाजारों के लिए राजनीतिक जोखिम पूंजी की लागत को काफी हद तक बढ़ा सकता है।
- सुरक्षा अक्सर सरकारों की खस्ता हाल कारोबारों को, रोजगार खत्म होने की संवेदनशीलता के कारण, सहारा देकर चलाने की प्रवृत्ति होती है, जबकि आर्थिक रूप से उनका बंद हो जाना ही हितकर होता है।
- बाजार अनुशासन का अभाव. खराब ढंग से प्रबंधित सरकारी कंपनियां निजी कंपनियों के उस अनुशासन से अलग होती हैं, जिसके अनुसार दिवालिया होने पर उनके प्रबंधन को हटाया जा सकता है, या किसी प्रतियोगी द्वारा उसे खरीद लिया जाता है। निजी कंपनियां अधिक से अधिक जोखिम लेने और फिर यदि खतरे और अधिक बढ़ जायें तो लेनदारों के खिलाफ दिवालियापन संरक्षण लेने में भी सक्षम होती हैं।
- प्राकृतिक एकाधिकार. प्राकृतिक एकाधिकार के अस्तित्व का मतलब यह नहीं है कि यह क्षेत्र राज्य के स्वामित्व वाले ही हों। सार्वजनिक अथवा निजी, सभी कंपनियों के प्रतिस्पर्द्धा-विरोधी व्यवहारों से निपटने के लिए, सरकारें स्पर्द्धा-रोधी कानून बना सकती हैं या इससे निपटने के लिए सुसज्जित हैं।
- धन का केंद्रीकरण. खासकर वाउचर निजीकरण में, सफल उद्यमों से लाभ और उनके स्वामित्व की प्रवृत्ति छितराने की और विविधतापूर्ण होती है। अधिक निवेश साधनों की उपलब्धता पूंजी बाजार को बढ़ावा देती है और तरलता तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देती है।
- राजनीतिक प्रभाव. राष्ट्रीयकृत उद्योगों में राजनीतिक नेताओं के राजनीतिक अथवा लोकलुभावन कारणों से हस्तक्षेप की प्रवृत्ति होती है। उदाहरणों में, एक उद्योग को स्थानीय उत्पादकों से आपूर्ति खरीदने के लिए बाध्य करना (जब कि बाहर से खरीदने की तुलना में यह अधिक महंगा हो सकता है), एक उद्योग को मतदाताओं को संतुष्ट करने या मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए अपनी कीमतें/किराए स्थिर करने के लिए, बेरोजगारी कम करने के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने, या इसके प्रचालन को सीमांत निर्वाचन क्षेत्रों में ले जाने के लिए बाध्य करना शामिल है।
- मुनाफा. निगम अपने शेयरधारकों के लिए लाभ उत्पन्न करने के लिए मौजूद हैं। निजी कंपनियां उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्द्धा की बजाय अपने उत्पाद खरीदने के लिए लुभा कर लाभ बनाती हैं (या अपने उत्पादों की प्राथमिक मांग बढ़ा कर, या कीमतें घटाकर). निजी निगम यदि अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं की पूर्ति अच्छी करते हैं, तो वे आमतौर पर अधिक लाभ कमाते हैं। विभिन्न आकारों के निगम सीमांत समूहों पर ध्यान केंद्रित करने और उनकी मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न बाजार स्थानों

को लक्ष्य बनाते हैं। इसलिए अच्छे निगमित प्रशासन वाली एक कंपनी अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए प्रोत्साहित होती है।

- नौकरियों के लाभ. जब अर्थव्यवस्था अधिक कुशल हो जाती है, अधिक लाभ प्राप्त होते हैं तथा सरकारी सब्सिडी की जरूरत नहीं रहती, कम करों की जरूरत होती है, निवेश और खपत के लिए अधिक निजी धन उपलब्ध होता है, एक अधिक विनियमित अर्थव्यवस्था की तुलना में बेहतर भुगतान वाली नौकरियों का सृजन होता है।^[6]

विरोध

निजीकरण के विरोधी इस आधार पर कि सरकार प्रतिनिधि मालिक होने के नाते लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, सार्वजनिक सेवाओं को अच्छी तरह चलाने के लिए सरकार के पास प्रोत्साहनों की कमी होने के दावे का विरोध करते हैं। यह तर्क दिया गया है कि जो सरकार राष्ट्रीयकृत उद्यमों को खराब ढंग से चलाएगी वह लोगों का समर्थन और मत खो देगी, जबकि उद्यमों को अच्छी तरह चलाने वाली सरकारों को लोगों का समर्थन और मत मिलेंगे. इस प्रकार, लोकतांत्रिक सरकारों के पास भी, भविष्य के चुनावों के दबाव के कारण राष्ट्रीयकृत कंपनियों में अधिकतम दक्षता बढ़ाने के रूप में प्रोत्साहन उपलब्ध हैं।

निजीकरण के कुछ विरोधियों का मानना है कि कुछ सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को मुख्य रूप से सरकार के हाथ में रहना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की उन तक पहुंच हो सके (जैसे कानून प्रवर्तन, बुनियादी स्वास्थ्य तथा बुनियादी शिक्षा). इसी तरह, कुछ निजी वस्तुओं और सेवाओं को निजी क्षेत्र के हाथों में रहना चाहिए। जब सरकार बड़े पैमाने पर समाज के लिए सार्वजनिक माल और सेवाएं उपलब्ध कराती है, तो एक सकारात्मक बाह्यता होती है, जैसे रक्षा और रोग नियंत्रण. प्राकृतिक एकाधिकार के लिए अपने स्वभाव के कारण ही वे निष्पक्ष प्रतियोगिता के अधीन नहीं हैं और इन्हें राज्य द्वारा प्रशासित करना ही बेहतर है।^[17]

निजीकरण विरोधी परिप्रेक्ष्य में नैतिक मुद्दा नियंत्रित करना सामाजिक समर्थन मिशन के लिए जिम्मेदार नेतृत्व की जरूरत है। बाजार की पारस्परिक क्रियाएं निजी स्वार्थ से निर्देशित होती हैं और एक स्वस्थ बाजार में सफल प्रदर्शकों को जितना बाजार सहन कर सके, अधिकतम मूल्य वसूल करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। निजीकरण विरोधियों का मानना है कि यह मॉडल सामाजिक सहायता के लिए सरकारी मिशन, जिसका प्राथमिक उद्देश्य समाज को सस्ती और गुणवत्ता वाली सेवा देना है, के साथ संगत नहीं है।

कई निजीकरण विरोधियों ने इस प्रक्रिया में अंतर्निहित भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति के खिलाफ भी चेतावनी दी है। कई क्षेत्र जो सरकार प्रदान कर सकती है, अनिवार्य रूप से लाभरहित हैं, एक तरीका जिससे निजी कंपनियां उनमें काम कर सकें, वह अनुबंध या भुगतान रोकने के माध्यम से हो सकता है। इन मामलों में, एक विशेष परियोजना में निजी फर्म के प्रदर्शन को उनके प्रदर्शन से हटा दिया जाएगा और गबन और खतरनाक लागत कटौती के उपाय करके लाभ को अधिकतम किया जा सकता है।

इसके अलावा, बड़े निगम निर्णयकर्ताओं को यह विश्वास दिलाने के लिए कि निजीकरण एक समझदार विचार है, जन संपर्क पेशेवरों को, भुगतान कर सकते हैं। निगमों के पास आम तौर पर निजीकरण विरोधियों की तुलना में कहीं अधिक विशेषज्ञ कथन, विज्ञापन, सम्मेलन और अन्य प्रचार हेतु संसाधन हैं।

कुछ इस ओर भी संकेत करेंगे कि सरकार के कुछ कार्यों का निजीकरण होने से समन्वय प्रभावित होता है और कंपनियों पर कार्य प्रदर्शन की विशिष्टीकृत और सीमित क्षमता के साथ उनके उपयुक्त न होने का आरोप लगाते हैं। युद्ध से विदीर्ण देश के बुनियादी ढांचे के पुनर्निर्माण में उदाहरण के लिए, एक निजी फर्म, के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए या तो सुरक्षा किराये पर लेनी होती है जो निश्चित रूप से सीमित और उनके कार्यों को जटिल बनाने वाली होगी, अथवा सरकार के साथ समन्वय करना होता है, जो फर्म और सरकार के बीच साझा कमान ढांचे की कमी के कारण बहुत मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ एक

सरकारी एजेंसी के पास सुरक्षा के लिए बुलाने को पूरी सेना है, जिसकी कमान श्रृंखला स्पष्ट रूप से परिभाषित है। विरोधियों का कहना है कि यह एक झूठ दावा है: कितनी ही पुस्तकों में सरकारी विभागों के बीच कमजोर संगठन के संदर्भ हैं (उदाहरण के लिए, हरीकेन कैटरीना की घटना)।

हालांकि निजी कंपनियां सरकार के समान अच्छा माल या सेवा प्रदान करेंगी, निजीकरण के विरोधी सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं और संपत्तियों को पूरी तरह से निजी हाथों में सौंपने के लिए निम्नलिखित कारणों से सतर्क हैं:

- कार्यक्षमता (परफॉर्मेंस) एक लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार संसद या विधायिका या कांग्रेस के माध्यम से लोगों के प्रति जवाबदेह है और राष्ट्र की संपत्ति की रक्षा करने के लिए प्रेरित है। लाभ का लक्ष्य सामाजिक उद्देश्यों के सामने गौण हो सकता है।
- सार्वजनिक सामान और सेवाओं की बढ़ी हुई बाजार दक्षता. एक सार्वजनिक संगठन की सैमुएलसन दशा तथा सीमांत सामाजिक लाभ वक्र के अनुसार अधिक सार्वजनिक सामान और सेवाओं के उत्पादन की प्रवृत्ति होती है। इसका परिणाम समाज के लिए बेहतर सकारात्मक बाह्यता होती है। दूसरी तरफ, एक निजी फर्म, पर्याप्त सार्वजनिक माल और सेवाएं प्रदान नहीं करती क्योंकि इससे उन्हें सीमांत निजी लाभ वक्र या निजी मांग वक्र प्राप्त होता है। एक निजी फर्म अधिक लाभ के लिए कम मात्रा प्रदान करती है। इसलिए पूरे समाज के लिए सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को और अधिक कुशलता से एक सार्वजनिक संगठन द्वारा ही प्रदान किया जाता है। (कोई भी बाजार समाज के लिए अधिक कुशल होता है जब सीमांत सामाजिक लाभ, सीमांत सामाजिक लागत के बराबर होता है, एमएसबी (MSB)= एमएससी (MSC))
- सुधार. सरकार कार्य-प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रेरित होती है क्योंकि अच्छी तरह से चलने वाले कारोबार से राज्य के राजस्व में योगदान मिलता है।
- भ्रष्टाचार. सरकार के मंत्री और नागरिक सेवक उच्चतम नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए बाध्य हैं और ईमानदारी के मानकों की गारंटी आचार संहिता और हितों की घोषणाओं के माध्यम से हो जाती है। हालांकि, बेचने की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी हो सकती है, क्रेता और नागरिक व्यक्तिगत लाभ के लिए बिक्री को नियंत्रित कर सकते हैं।
- उत्तरदायित्व निजी कंपनी पर जनता का किसी प्रकार का नियंत्रण या निरीक्षण नहीं होता।
- नागरिक स्वतंत्रता का सवाल. एक लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार संसद के माध्यम से लोगों के लिए जवाबदेह है और नागरिक स्वतंत्रता पर खतरा होने पर हस्तक्षेप कर सकती है।
- लक्ष्य. सरकार पूरे राष्ट्र के लाभ के लिए राज्य कंपनियों का उपयोग साधन के रूप में सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कर सकती है।
- पूंजी सरकारें वित्तीय बाजारों में पैसा सबसे सस्ती दर पर उठा कर फिर से राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को उधार दे सकती हैं।
- सामरिक और संवेदनशील क्षेत्र. सरकारों ने सामरिक महत्व या संवेदनशील स्वभाव की वजह से कुछ कंपनियों/उद्योगों को सार्वजनिक नियंत्रण में रखा है।
- आवश्यक सेवाओं में कटौती. यदि कोई सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी सभी नागरिकों के लिए एक अनिवार्य सेवा (जैसे पानी की आपूर्ति) प्रदान करती है, का निजीकरण कर दिया जाता है, तो इसके नए मालिक के लिए, उन लोगों के संदर्भ में जो सेवा का भुगतान करने की स्थिति में नहीं हैं या जिन क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति लाभजनक नहीं है, सामाजिक दायित्व छोड़ने की स्थिति पैदा हो सकती है।
- प्राकृतिक एकाधिकार. यदि प्राकृतिक एकाधिकार मौजूद रहता है तो सही प्रतियोगिता के रूप में परिणाम निजीकरण नहीं रहेगा।

- धन का केंद्रीकरण. सफल उद्यमों से प्राप्त होने वाला लाभ अंत में साधारण लोगों तक पहुंचने की बजाए निजी, अक्सर विदेशी हाथों तक पहुंचता है।
- राजनीतिक प्रभाव. सरकारें अधिक आसानी से राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों पर दबाव डाल कर लागू करने के लिए सरकार की नीति को लागू करने में मदद कर सकती हैं।
- आकार में कटौती. निजी कंपनियां अक्सर लाभप्रदता और सेवा स्तर के बीच संघर्ष का सामना करती हैं और अल्पकालिक घटनाओं पर आवश्यकता से अधिक प्रतिक्रिया कर सकती हैं। एक राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी लंबी अवधि का दृष्टिकोण रखती है और शायद इस तरह अल्पकालिक नुकसान से निबटने के लिए कम से कम रखरखाव या कर्मचारियों की लागत, प्रशिक्षण आदि में कटौती करने की संभावना बहुत ही कम होती है। कई निजी कंपनियों ने अपना आकार छोटा कर दिया है लेकिन रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं।
- लाभ. निजी कंपनियों का अधिकतम लाभ के अलावा कोई लक्ष्य नहीं होता है। एक निजी कंपनी बहुसंख्यकों की आवश्यकताओं की बजाय उन की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगी जो भुगतान करने के सर्वाधिक इच्छुक (और सक्षम) हैं और इस प्रकार ऐसा लोकतंत्र विरोधी है। वस्तु जितनी ज्यादा आवश्यक होगी, उसकी मांग की मूल्य-सापेक्षता उतनी ही कम होगी, क्योंकि क्रेता उसे खरीदेगा ही, मूल्य चाहे जो हो। जिस स्थिति में मांग में लचीलापन कीमत के मामले में शून्य हो जाता है (बिल्कुल स्थिर), आपूर्ति का मांग का हिस्सा और मांग के सिद्धांत काम नहीं करते।
- निजीकरण और गरीबी. कई अध्ययनों में यह माना गया है कि निजीकरण के साथ विजेता और पराजित जुड़े होते हैं। हारने वालों की संख्या- जो गरीबी के आकार और गंभीरता में जुड़ जाएगी- अप्रत्याशित रूप से बड़ी हो सकती है, अगर निजीकरण की विधि और प्रक्रिया तथा इसे लागू करने के तरीके में गंभीर दोष रह गए तो (पारदर्शिता के अभाव में राज्य के स्वामित्व वाली संपत्ति को राजनीतिक संबंध रखने वाले लोगों द्वारा अत्यंत छोटी धनराशि के बदले हथिया लिया जाएगा, किसी नियामक संस्था की अनुपस्थिति के कारण एकाधिकार किराया सार्वजनिक क्षेत्र से निजी क्षेत्र में चला जाता है, निजीकरण प्रक्रिया के अनुचित डिजाइन और अपर्याप्त नियंत्रण के कारण यह संपत्ति की हेराफेरी होती है।^[7]
- नौकरियों की हानि. अतिरिक्त निजीकरण के बाद बिना सरकारी सहायता के, अतिरिक्त वित्तीय भार के कारण सार्वजनिक कंपनियों के विपरीत, कंपनी में और अधिक पैसा रखने के लिए नौकरियां समाप्त हो जायेंगी।

मध्यवर्ती दृष्टिकोण

अन्य लोग इस पर विवाद नहीं करते कि अच्छी तरह चल रही लाभ-कमाने वाली इकाइयां, किसी अकुशल सरकारी नौकरशाही या एनजीओ (NGO) के मुकाबले मजबूत निगमित सुशासन के साथ अधिक दक्ष होती हैं, हालांकि व्यवहार में निजीकरण के कई क्रियान्वयनों के परिणामस्वरूप और/या अक्षम या भ्रष्ट- लाभके-लिए प्रबंधन के लिए, सार्वजनिक संपत्ति की कौड़ियों के भाव बिक्री होती है।^[15]

विकसित या न्यूनतम भ्रष्ट अर्थव्यवस्थाएं

सूचना की विषमता के कारण एक शीर्ष कार्यकारी आसानी से एक संपत्ति के अनुमानित मूल्य को कम कर सकता है। अनुमानित खर्च के लेखांकन में तेजी लाकर, अनुमानित आय के लेखांकन में देरी करके, अस्थायी रूप से कंपनी की लाभप्रदता कमजोर दिखाने के लिए तुलन-पत्र से बाहर लेन-देन कर के, या सीधे भविष्य की आय का गंभीर रूप से रूढ़िवादी (जैसे, निराशावादी) अनुमान प्रस्तुत करके एक कार्यकारी ऐसा कर सकता है। इस तरह प्रतिकूल लगने वाली आय की खबर (कम से कम अस्थायी रूप से) बिक्री मूल्य को कम कर देगी. (ऐसा फिर से सूचना की विषमता के कारण हुआ है क्योंकि एक शीर्ष कार्यकारी के लिए यह आम है कि अपने आय के पूर्वानुमान की झूठी तसवीर पेश करने के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं।) आम तौर पर किसी के लेखांकन और आय अनुमान में 'अत्यधिक संकीर्ण' होने पर बहुत कम कानूनी खतरे हैं।

जब इकाई (संपत्ति) को निजी संस्था द्वारा लिया जाता है - एक नाटकीय रूप से कम कीमत पर - नए निजी मालिक को शीर्ष कार्यकारी के बिक्री मूल्य को कम करने के कृत्य (चोरी-छिपे) से एक अप्रत्याशित लाभ होता है। इस प्रकार दसियों अरब डॉलर (संदिग्ध रूप से) पिछले मालिकों (सार्वजनिक) से अधिग्रहण करने वाले को स्थानांतरित हो जाते हैं। पूर्व शीर्ष अधिकारी को तब कौड़ियों के दाम बिक्री, जो कभी-कभी एक-दो साल के काम के बदले दसियों या सैकड़ों लाख डॉलर हो सकती है, करने वाले काम की अध्यक्षता करने के लिए गोल्डन हैंडशेक (स्वर्णिम विदाई) से पुरस्कृत किया जाता है। (फिर भी, यह अधिग्रहण करने वाले के लिए उत्कृष्ट सौदा है जिससे उसे अब विदा होते शीर्ष कार्यकारी के प्रति अति उदार होने की प्रतिष्ठा मिलने जा रही है।)

जब एक सार्वजनिक रूप से धारित संपत्ति, पारस्परिक या लाभरहित संगठन का निजीकरण होता है तो शीर्ष अधिकारी अक्सर जबरदस्त मौद्रिक लाभ लेते हैं। कार्यकारी इस प्रक्रिया को इकाई को वित्तीय संकट में दिखा कर, सुगम बना देते हैं- इससे बिक्री मूल्य (क्रेता के लाभ के लिए) घट जाता है और उसे लाभरहित बना देते हैं, तथा जिससे सरकार द्वारा उसे बेचने की संभावना बढ़ जाती है।

विडंबना यह है कि, इस सार्वजनिक धारणा से सार्वजनिक संपत्ति को बेच देने की राजनीतिक इच्छाशक्ति को बल मिलता है कि निजी संस्थाएं अधिक कुशलता से संचालित होती हैं। पुनः विषम सूचना के कारण नीति निर्माता और आम जनता देखते हैं कि एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी जो एक वित्तीय आपदा थी - निजी क्षेत्र द्वारा चमत्कारिक ढंग से (आम तौर से पुनर्बिक्री) कुछ ही दिन में उसकी काया पलट ही गई।^[11,12]

अविकसित या अत्यधिक भ्रष्ट अर्थव्यवस्थाएं

बहुत अधिक भ्रष्टाचार वाले एक समाज में, निजीकरण से वर्तमान में सत्तारूढ़ सरकार और इसके समर्थकों को स्वामित्व वाली परिसंपत्ति के शुद्ध वर्तमान मूल्य का एक बड़ा भाग बेईमानी से जनता से ले कर उनकी पसंदीदा ताकत के दलालों के खाते में डालने का मौका मिल जाता है। निजीकरण के बिना, भ्रष्ट अधिकारियों को समय के साथ धीरे धीरे अपनी भ्रष्ट कमाई की फसल काटनी होती। अतः एक कुशल निजीकरण इस पर निर्भर करता है कि वर्तमान सरकारी अधिकारियों में भ्रष्टाचार का वर्तमान स्तर बहुत कम हो, क्योंकि इसमें भ्रष्ट राशि के कहीं अधिक कुशल निष्कर्षण की संभावना होती है।

बेशक, भ्रष्ट सरकारें अन्य तरीकों से भी भ्रष्ट कमाई का बड़ी कुशलता के साथ निष्कर्षण कर सकती हैं - विशेष रूप से बेतहाशा उधार लेकर अपने बहुत ज्यादा पसंदीदा समर्थकों के अनुबंधों में खर्च करके (या कर बचतों पर या सब्सिडीज पर या अन्य मुफ्त विज्ञापन वस्तुओं पर). दशाब्दियों पूर्व भ्रष्ट हस्तांतरण के द्वारा लिया गया ऋण करदाताओं की पीढ़ियों को चुकाना पड़ता है। जाहिर है, इस का परिणाम सार्वजनिक संपत्ति की बिक्री में हो सकता है।...

अंत में, जनता एक ऐसी सरकार के साथ रह जाती है, जो उन पर भारी कर लगाती है और बदले में कुछ नहीं देती. ऋण वापसी अंतरराष्ट्रीय समझौतों और आईएमएफ (IMF) जैसी एजेंसियों द्वारा लागू की जाती है। बुनियादी ढांचा और रखरखाव का बलिदान हो जाता है - समयांतर में देश की आर्थिक क्षमता और क्षीण हो जाती है।

साहित्य की समीक्षा^{[8][9]} से पता चलता है कि अच्छी तरह से वाकिफ उपभोक्ताओं के साथ प्रतिस्पर्धी उद्योग, के साथ निजीकरण की दक्षता में लगातार सुधार होता है। ऐसे दक्षता लाभ का मतलब है जीडीपी (GDP) में एकबारगी वृद्धि, किंतु सुधरे हुए प्रोत्साहनों के माध्यम से नया करने और लागत कम करने के साथ आर्थिक विकास की दर बढ़ने की भी प्रवृत्ति होती है। जिन प्रकार के उद्योगों पर यह सामान्यतः लागू होती है उनमें शामिल हैं विनिर्माण और खुदरा बिक्री. यद्यपि आमतौर पर इन दक्षता लाभों के साथ सामाजिक लागत भी संबद्ध हैं^[10], कई अर्थशास्त्रियों का तर्क है कि इन से सरकार के उचित समर्थन द्वारा पुनर्वितरण और संभवतः पुनर्प्रशिक्षण के माध्यम से निपटा जा सकता है।

प्राकृतिक एकाधिकार और सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों में (जैसे, संयुक्त राज्य अमेरिका में यात्री रेल), निजीकरण के परिणाम बहुत अधिक मिश्रित हैं, क्योंकि उदार आर्थिक सिद्धांत में निजी एकाधिकार भी बहुत कुछ सार्वजनिक की तरह ही व्यवहार करता है। सरकार वास्तव में सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं की एक और अधिक प्राकृतिक प्रदाता के रूप में देखी जाती है। हालांकि, मौजूदा सार्वजनिक क्षेत्र के प्रचालन की क्षमता पर प्रश्न किया जा सकता है कि उसमें परिवर्तनों की आवश्यकता है। परिवर्तन में अन्य बातों के साथ ये शामिल हो सकती हैं, संबंधित सुधारों जैसे अधिक पारदर्शिता और प्रबंधन की जवाबदेही, एक बेहतर लागत-लाभ विश्लेषण, बेहतर आंतरिक नियंत्रण, नियामक प्रणाली और बजाय खुद के निजीकरण के बेहतर वित्तपोषण।

राजनीतिक भ्रष्टाचार के संबंध में, यह एक विवादास्पद मुद्दा है कि क्या सार्वजनिक क्षेत्र का आकार स्वतः भ्रष्टाचार में परिणत होता है। नॉर्डिक देशों में बड़े सार्वजनिक क्षेत्र हैं लेकिन भ्रष्टाचार कम है। हालांकि, अच्छे और प्रायः सरल विनियम, राजनीतिक अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता, उच्च सरकारी जवाबदेही और पारदर्शिता के कारण इन देशों के व्यवसाय करने की सरलता का सूचकांक का स्कोर उच्च रहता है। नॉर्डिक देशों में सफल, भ्रष्टाचारमुक्त निजीकरण और सरकारी उद्यमों का पुनर्गठन भी दिखाई देता है। उदाहरण के लिए, दूरसंचार एकाधिकार की समाप्ति के परिणामस्वरूप कई नए उद्यमियों ने बाजार में प्रवेश किया है और मूल्य और सेवा के साथ तीव्र प्रतिस्पर्धा हुई है।

इसके अलावा भ्रष्टाचार के बारे में भी, बिक्री खुद भव्य भ्रष्टाचार के लिए एक बड़ा अवसर देती हैं। रूस और लैटिन अमेरिका में निजीकरण के साथ राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों की बिक्री के दौरान बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी आया। राजनीतिक संबंधों वाले लोगों ने अनुचित ढंग से बड़ा धन प्राप्त किया, जिसने इन क्षेत्रों में निजीकरण को बदनाम किया है। जबकि मीडिया ने व्यापक रूप से बिक्री के साथ जुड़े भव्य भ्रष्टाचार के बारे में सूचित किया है, अध्ययनों का कहना है कि बढ़ी हुई परिचालन दक्षता के अलावा दैनिक क्षुद्र भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, या निजीकरण के बिना बड़ा हो सकता है और गैर-निजीकरण क्षेत्रों में भ्रष्टाचार अधिक प्रचलित है। इसके अलावा, प्रमाण बताते हैं कि जिन देशों में कम निजीकरण हुआ है वहां अतिरिक्त कानूनी और अनौपचारिक गतिविधियां अधिक प्रचलित हैं।^[11]

परिणाम

विकल्प

सार्वजनिक उपयोगिता

उद्यम एक सार्वजनिक उपयोगिता के रूप में रह सकता है।

लाभ-रहित

एक निजी लाभ रहित संगठन उद्यम का प्रबंधन कर सकता है।

नगरनिगमीकरण

नियंत्रण नगर निगम सरकार को स्थानांतरित करना

आउटसोर्सिंग या उप ठेका

राष्ट्रीय सेवाएं अपने कार्यों को निजी उद्यमों को उप अनुबंध या बाहरी-स्रोत को ठेके पर दे सकती हैं। इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण ब्रिटेन का है जहां कई नगरपालिकाओं ने कचरा संग्रहण या पार्किंग जुर्माना लगाने के काम के लिए निजी कंपनियों को अनुबंधित कर दिया है। इसके अलावा, ब्रिटिश सरकार ने मुख्यतः नये अस्पतालों का निर्माण और प्रचालन निजी कंपनियों को ठेके पर दे कर राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के कार्यों में निजी

क्षेत्र को अधिक शामिल किया है। वहां वर्तमान एनएचएस मानव संसाधन पर भार को कम करने के लिए, इसकी लागत को कवर करते हुए मरीजों को निजी शल्य चिकित्सालयों में भेजने का भी प्रस्ताव है।

आंशिक स्वामित्व

एक उद्यम का निजीकरण किया जा सकता है लेकिन सरकार उसके एवज में नई कंपनी के शेयरों की काफी संख्या अपने पास रख लेती है। यह विशेष रूप से फ्रांस में एक उल्लेखनीय घटना है, जहां सरकार प्रायः निजी उद्योगों में एक "अवरोधक हिस्सेदारी" अपने पास रखती है। जर्मनी में, सरकार ने ड्यूश टेलीकॉम का छोटे-छोटे भागों में निजीकरण किया है और लगभग एक तिहाई कंपनी अभी भी उसके पास है। 2005 से उत्तरी राइन-वेस्टफेलिया राज्य भी, जैसा कि दावा किया गया है, बढ़ती लागत को नियंत्रित करने के प्रयास में, ऊर्जा कंपनी ई.ऑन (E.ON) के शेयर खरीदने की योजना बना रहा है।

जबकि आंशिक निजीकरण एक विकल्प हो सकता है, यह अक्सर अधिक पूर्ण निजीकरण की ओर एक कदम है। यह व्यापार को एक निर्बाध संक्रमण अवधि प्रदान करता है, जिसके दौरान वह धीरे-धीरे बाजार की प्रतिस्पर्धा के साथ समायोजन कर सकता है। राज्य के स्वामित्व वाली कुछ कंपनियां इतनी बड़ी हैं कि वहां के बाजार के बाकी हिस्सों से, सबसे अधिक तरल बाजारों में भी, नकदी चूसने का खतरा है, इस कारण क्रमिक निजीकरण को पसंद किया जा सकता है। बहु-चरण निजीकरण के पहले भाग में भी, पहले अवसर पर कम-मूल्य की शिकायतों को कम करने के लिए उद्यम के लिए एक मूल्यांकन स्थापित होगा।

अनुबंधित सेवाओं के आंशिक निजीकरण के कुछ उदाहरणों में, राज्य के स्वामित्व वाली सेवा के कुछ भाग निजी क्षेत्र के ठेकेदारों द्वारा प्रदान किये जाते हैं, लेकिन सरकार यह क्षमता रखती है कि अनुबंध अंतराल पर स्वयं प्रचालित कर सके, यदि वह ऐसा करना चाहे। आंशिक निजीकरण का एक उदाहरण होगा स्कूल बस सेवा अनुबंध का कोई रूप, ऐसी कोई व्यवस्था जिसमें उपकरण और अन्य सरकारी पूंजी से खरीदे गए तथा सरकारी इकाई के पास पहले से उपलब्ध संसाधनों का एक समयावधि में सेवा प्रदान करने के लिए ठेकेदार द्वारा उपयोग किया जाता है, लेकिन स्वामित्व सरकारी इकाई के पास ही रहता है। आंशिक निजीकरण के इस रूप में इस चिंता को दूर किया गया है कि एक बार एक प्रचालन अनुबंधित होने पर, सरकार पर्याप्त प्रतिस्पर्धी बोली प्राप्त करने में असमर्थ हो सकती है और राज्य के स्वामित्व के तहत पूर्व प्रचालन की तुलना में कम वांछनीय शर्तें रखनी पड़ सकती हैं। उस परिदृश्य के अंतर्गत सरकार के लिए एक उलट निजीकरण संभव हो जाएगा। [10,11]

सार्वजनिक निजी भागीदारी

उल्लेखनीय उदाहरण

इतिहास का सबसे बड़ा निजीकरण जापान डाक सेवा का हुआ है। यह देश की सबसे बड़ी नियोक्ता थी और सभी जापानी सरकारी कर्मचारियों में से एक तिहाई जापान डाक सेवा के लिए काम करते थे। जापान डाक सेवा को अक्सर दुनिया में निजी बचत का सबसे बड़ा धारक बताया जाता था।

प्रधानमंत्री कोइजुमी जूनीचिरो इसका निजीकरण करना चाहते थे क्योंकि इसे अकुशल^[किसके द्वारा?] और भ्रष्टाचार का स्रोत माना गया था। सितंबर 2003 में, कोइजुमी मंत्रीमंडल ने जापान पोस्ट का चार अलग कंपनियों में बंटवारे का प्रस्ताव रखा: एक बैंक, एक बीमा कंपनी, एक डाक सेवा कंपनी और एक चौथी कंपनी शेष तीनों के खुदरा स्टोरफ्रंट्स के रूप में डाकघरों को संभालने के लिए।

बाद ऊपरी सदन द्वारा निजीकरण अस्वीकार कर देने के बाद कोइजुमी ने 11 सितंबर 2005 को राष्ट्रव्यापी चुनाव अधिसूचित कर दिए। उन्होंने घोषणा की कि ये चुनाव डाक निजीकरण पर एक जनमत संग्रह होंगे।

तदनन्तर कोइजुमी ने जुनाव जीता, आवश्यक सुपरबहुमत और सुधार करने का जनमत प्राप्त किया और अक्टूबर 2005 में 2007 में जापान डाक सेवा का निजीकरण करने का बिल पारित हो गया।^[12]

1987 में निप्पॉन टेलीग्राफ और टेलीफोन के निजीकरण के समय वित्तीय इतिहास की सबसे बड़ी हिस्सेदारी की पेशकश शामिल है।^[13] दुनिया की 20 सबसे बड़ी सार्वजनिक शेयर पेशकश में से 15 में टेलीकॉम का निजीकरण किया गया है।^[13]

ब्रिटेन की सबसे बड़ी सार्वजनिक शेयर पेशकश ब्रिटिश टेलीकॉम और ब्रिटिश गैस के निजीकरण थे। फ्रांस में सबसे बड़ी सार्वजनिक शेयर पेशकश फ्रांस टेलीकॉम की थी।

नकारात्मक प्रतिक्रियाएं

प्रमुख सार्वजनिक सेवा क्षेत्रों, जैसे पानी और बिजली के निजीकरण के कई मामलों में निजीकरण प्रस्तावों को विपक्षी राजनीतिक दलों और नागरिक समाज समूहों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, जिनमें से अधिकतर इन्हें प्राकृतिक एकाधिकार मानते हैं। अभियानों में आमतौर पर प्रदर्शन और लोकतांत्रिक राजनीतिक गतिविधियां शामिल हैं, कभी कभी अधिकारी हिंसा का उपयोग करते हुए विपक्ष को दबाने के प्रयास करते हैं (जैसे बोलीविया में 2000 के कोचाबम्बा विरोध और जून 2002 में अरेकिपा, पेरू के विरोध). विपक्ष को अक्सर मजदूर संघों का मजबूत समर्थन मिलता है। विरोध आमतौर पर पानी के निजीकरण के खिलाफ सर्वाधिक मजबूत है- कोचाबम्बा के साथ हाल के उदाहरणों में हैती, घाना और उरुग्वे (2004) शामिल हैं। उत्तरार्द्ध मामले में एक नागरिक समाज द्वारा शुरू जनमत संग्रह में पानी निजीकरण प्रतिबंध अक्टूबर 2004 में पारित किया गया था।^[9,10]

प्रतिगमन

एक अनुबंधित स्वामित्व उद्यम या सेवाओं के सरकारी स्वामित्व में प्रतिगमन और/या प्रावधान को उलट निजीकरण या राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। ऐसी स्थिति अक्सर तब होती है जब एक निजीकरण ठेकेदार आर्थिक रूप से विफल रहता है और/या सरकारी इकाई, सेवाओं के सरकारी स्वामित्व या आत्म-प्रचालन के समय की कीमतों से नीचे कीमतों पर संतोषजनक सेवाएं खरीदने में विफल रहती है। एक अन्य घटना तब हो सकती है जब निजीकरण के तहत व्यवहार्य से अधिक नियंत्रण को सरकारी यूनिट के सर्वोत्तम हित में निर्धारित किया जाता है।

जब सबसे अधिक संभावित प्रदाता गैर घरेलू या अंतरराष्ट्रीय निगम या संस्था हों तो राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताएं उलट निजीकरण क्रियाओं का स्रोत हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, 2001 में, 11 सितंबर के हमलों की प्रतिक्रिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में तत्कालीन निजी हवाई अड्डा सुरक्षा उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया गया था और परिवहन सुरक्षा प्रशासन के प्राधिकार के अधीन रखा गया था।

निष्कर्ष

उच्च शिक्षा नीति अथवा हायर एजुकेशन पॉलिसी (higher education policy) उस शिक्षा नीति के लिए प्रयुक्त शब्दावली है जो उच्च शिक्षा संस्थानों यथा विश्वविद्यालयों, शोध अथवा तकनीकी संस्थानों आदि के लिए होती है। इसमें उनके सामाजिक रूप से संचालन, वित्त पोषण एवं नियमबद्ध होना शामिल है। सामान्य वैश्विक शोध में उच्च शिक्षा को तीन भागों में विभक्त किया गया है। ये तीन भाग एंग्लो-सैक्सन, महाद्वीपीय और स्कैंडिनेवियाई शिक्षा प्रणालियाँ हैं।^{[1][2]}

ऐंग्लो-सैक्सन शिक्षा प्रणाली

इसे सामान्यतः आंग्ल-अमेरिकी प्रणाली भी कहते हैं। इसमें शिक्षा प्रणाली सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में होती है और यह महंगी नहीं होने के साथ ये सभी के लिए है। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1948 में राधाकृष्णन समिति ने इसी प्रारूप में नीति को स्वीकृत करने की अनुशंसा की थी जो बाद में लागू हुई।^[3]

महाद्वीपीय शिक्षा प्रणाली

यह शिक्षा प्रणाली केवल अभिजात वर्ग के लिए होती है और यह महंगी नहीं होने के साथ केवल सार्वजनिक होती है।

स्कैंडिनेवियाई शिक्षा प्रणाली

यह प्रणाली पूर्णतः सार्वजनिक होती है, सभी के लिए होती है लेकिन बहुत ही महंगी होती है।^[17]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. चौधरी, एफ़. एल. "भ्रष्ट नौकरशाही और कर प्रवर्तन का निजीकरण", 2006: पाठक सामबेश, ढाका
2. ↑ "Musselburgh Co-op in crisis as privatization bid fails". Co-operative News. 2005-11-01. मूल से 10 मार्च 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2008-05-21.
3. ↑ Edwards, Ruth Dudley (1995). The Pursuit of Reason: The Economist 1843-1993. Harvard Business School Press. पृष्ठ 946. आईएसबीएन 0-87584-608-4.
4. ↑ तुलना Bel, Germà (2006). "Retrospectives: The Coining of 'Privatisation' and Germany's National Socialist Party". Journal of Economic Perspectives. 20 (3): 187–194. डीओआई:10.1257/jep.20.3.187.
5. ↑ डेविड पार्कर द्वारा निजीकरण पर अंतर्राष्ट्रीय पुस्तिका, डेविड एस. साल
6. ↑ सेंट्रल यूरोप के बड़े पैमाने पर उत्पादन निजीकरण Archived 2009-10-18 at the Wayback Machine, हेरिटेज लेक्चर #352
7. ↑ डेंगडेविरेन (2006) "गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में निजीकरण पर पुनर्चर्चा". अंतर्राष्ट्रीय विकास का जर्नल खंड 18, 469-488
8. ↑ "Privatisation in Competitive Sectors: The Record to Date, World Bank Policy Research Working Paper No. 2860". John Nellis and Sunita Kikeri. World Bank. June 2002. मूल से 11 मार्च 2011 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 नवंबर 2010.
9. ↑ "From State To Market: A Survey Of Empirical Studies On Privatisation" (PDF). William L. Megginson and Jeffry M. Netter. Journal of Economic Literature. June 2001. मूल (PDF) से 2 अक्टूबर 2005 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 नवंबर 2010. Italic or bold markup not allowed in: `|publisher=` (मदद)
10. ↑ "Winners and Losers: Assessing the Distributional Impact of Privatisation, CGD Working Paper No 6" (PDF). Nancy Birdsall & John Nellis. Center for Global Development. March 9, 2006. मूल (PDF) से 23 जून 2005 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 24 नवंबर 2010.
11. ↑ प्रतिस्पर्धा क्षेत्रों में निजीकरण: तिथि का रिकॉर्ड: सुनीता किकेरी और जॉन नेलिस. विश्व बैंक नीति अनुसंधान वर्किंग पेपर 2860, जून 2002. निजीकरण और भ्रष्टाचार Archived 2011-07-18 at

the Wayback Machine. डेविड मार्टिमोर्ट और स्टीफन स्ट्रॉब. अमेरिका में एक करियर सिटी मैनेजर, रॉजर एल. केम्प ने निजीकरण शीर्षक से पुस्तकालय संदर्भ खंड लिखा: निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक सेवाओं का प्रावधान," जो मूलतः 1991 में प्रकाशित हुई तथा 2007 में पुनर्प्रकाशित हुई. इस खंड में, नगरपालिका सरकारों के बीच इस क्षेत्र में एक सर्वोत्तम प्रथाओं की राष्ट्रीय साहित्य खोज के आधार पर, डॉ॰ केम्प सिफारिश की कि यह उनके प्रशासक करदाताओं और नागरिकों के लिए चयनित लोक सेवाओं के निजी विकल्प ढूंढना चाहते हैं। उन्होंने महसूस किया कि शहर प्रबंधकों को बाजार में जाकर जबकि गुणवत्ता नगर पालिका द्वारा प्रदान की गई समान सेवा के अनुरूप रखते हुए, चयनित सार्वजनिक सेवाओं के लिए अनुबंध की लागत का निर्धारण करना चाहिए, कभी कभी केम्प ने लिखा, इसे और अधिक लागत प्रभावी है के लिए हैं कुछ सार्वजनिक सेवाएं निजी क्षेत्र द्वारा अनुबंध पर चलवाना अधिक किफायती होगा. कुछ मामलों में निजी क्षेत्र के लिए सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना कम खर्चीला हो सकता है, लेकिन इसका समाज को लाभ वास्तव में कम ही होगा.

12. ↑ ताकाहारा, "सभी आंखें जापान पोस्ट पर "Faiola, Anthony (2005-10-15). "Japan Approves Postal Privatization". Washington Post. The Washington Post Company. पृ॰ A10. मूल से 4 मार्च 2016 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2007-02-09.
13. ↑ विलियम एल. मेगिन्सन द्वारा निजीकरण के वित्तीय अर्थशास्त्र, पृष्ठ 205-206
14. अलेक्जेंडर, जेसन. 2009. शास्त्रीय व्यावहारिकता के लेंस के माध्यम से अनुबंध: स्थानीय सरकारी अनुबंध का अन्वेषण. अनुप्रयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं. टेक्सास राज्य विश्वविद्यालय. <https://web.archive.org/web/20100621122134/http://ecommons.txstate.edu/arp/288/>.
15. डोवालिना, जेसिका. 2006. आउट प्रोसेस करार में मिले नैतिक मुद्दों का आकलन. अनुप्रयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं. टेक्सास राज्य विश्वविद्यालय. <https://web.archive.org/web/20100625140633/http://ecommons.txstate.edu/arp/108/>.
16. सेजेर्फेल्ड, फ्रेडरिक. 2006. जल बिक्री के लिए: दुनिया के जल संकट को व्यापार और बाजार कैसे हल कर सकते हैं। स्टॉकहोम नेटवर्क. <https://web.archive.org/web/20120301074135/http://www.stockholm-network.org/downloads/events/d41d8cd9-Amigo%20Segerfeldt.pdf>
17. बर्नार्ड ब्लैक एट अल., 'रूसी निजीकरण और निगमित प्रशासन: क्या गलत हो गया? (2000) 52 स्टैनफोर्ड लॉ 1731 की समीक्षा



INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT



+91 99405 72462



+91 63819 07438



ijmrsetm@gmail.com

www.ijmrsetm.com